

देश के कई राज्यों में अगले पांच दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट



नई दिल्ली, एजेंसिया।

भारी बारिश की तगड़ी मार झेल रहे मध्य प्रदेश को पांच दिनों तक कोई बड़ी राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग की ओर से

जारी ताजा अपडेट के मुताबिक कम दबाव का एक क्षेत्र उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों पर बरकरार है। यही नहीं मानसूनी ट्रफ रेखा गंगानगर, नारनौल, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के ऊपर निम्न दबाव के क्षेत्र के केंद्र से गुजरती हुई वाराणसी, गया, बांकुरा के साथ दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की उत्तरपूर्वी खाड़ी की ओर जा रही है। इसकी वजह से अगले पांच दिनों तक मध्य प्रदेश में व्यापक बारिश होने की

संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी में कहा गया है कि बाढ़ की तगड़ी मार झेल रहे मध्य प्रदेश को अगले पांच दिनों तक मध्य प्रदेश में बारिश से निजात नहीं मिलने वाली है। यही नहीं अगले 24 घंटे के

दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि बाद में इसमें कमी आती जाएगी। यही नहीं पश्चिम बंगाल में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटे में ओडिशा और झारखंड जबकि 07 से 09 अगस्त के दौरान बिहार के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी में यह भी कहा गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में नौ अगस्त तक कहीं-कहीं मूसलाधार के साथ व्यापक बारिश होने की संभावना है। इसमें 10 अगस्त से और इजाफा होने की संभावना है। यही नहीं अगले पांच दिनों के दौरान उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। इसी अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में अलग-अलग भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। नौ अगस्त तक राजस्थान,

पंजाब, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि पांच और छह अगस्त को पूर्वी राजस्थान में अलग-अलग इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। उत्तरी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर जहां बारिश की संभावना है 10 तारीख तक हल्की बारिश जारी रह सकती है। अगले चार से पांच दिनों के दौरान प्रायद्वीपीय भारत और इससे सटे पूर्वी मध्य भारत (ओडिशा को छोड़कर) महाराष्ट्र और गुजरात में कम बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। वहीं मौसम का पूर्वानुमान जारी करने वाली एजेंसी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान, दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश और झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है।

राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने हॉकी में कांस्य पदक जीतने पर पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी

नई दिल्ली। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के 41 साल बाद तोकयो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि यह दिन हर भारतीय की स्मृतियों में हमेशा रहेगा। भारत ने कांस्य पदक के प्ले आफ मुकाबले में जर्मनी को 5-4 से हराकर पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया, ‘‘ 41 साल बाद ओलंपिक में पदक जीतने वाली हमारी पुरुष हॉकी टीम को बधाई। इस टीम ने बेहतरीन कौशल और दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन किया। इस जीत से देश में हॉकी के एक नये युग का उदय होगा और युवाओं को हॉकी खेलने तथा उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रेरणा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीयों को यह दिन हमेशा याद रहेगा। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘ ऐतिहासिक। यह दिन हर भारतीय की स्मृतियों में हमेशा रहेगा। कांस्य पदक जीतने के लिये हमारी पुरुष हॉकी टीम को बधाई। इससे उन्होंने पूरे देश को, खासकर युवाओं को रोमांचित किया है। भारत को अपनी हॉकी टीम पर गर्व है। खेलमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘‘ भारत के लिये करोड़ों चीयर्स। आखिर भारतीय हॉकी टीम ने कर दिया। हमारी पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक की इतिहास पुस्तिका में अपना नाम अंकित करा लिया। एक बार फिर से। हमें आप पर गर्व है।’’ गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, ‘‘ बधाई टीम इंडिया। यह पल हर भारतीय के लिये गर्व और हर्ष का है। हमारी पुरुष हॉकी टीम ने तोकयो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित किया है।



पहला कॉलम

सिख विरोधी दंगे के हर मृतक को 3.5 लाख और घायलों को मिर्नेगे 1.25 लाख रुपये

-बजट में दंगे के मुआवजे के भुगतान के लिये 4.5 करोड़ रुपये का प्रावधान:मुख्तार अब्बास नकवी

नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को बताया कि वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए लोगों के परिजनों को बड़े हुए मुआवजे के भुगतान के लिये 4.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में संतोष पाण्डेय के प्रश्न के उत्तर में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि केंद्र सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिये एक पुनर्वास पैकेज की घोषणा की थी। इस योजना में मृत्यु के प्रत्येक मामले के लिये 3.5 लाख रुपये और घायल होने के संबंध में 1.25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान शामिल है। नकवी ने कहा कि इस योजना में राज्य सरकारों के लिये मारे गये लोगों की विधवाओं और वृद्ध माता-पिता को 2,500 रुपये प्रति माह की एक समान दर पर जीवनभर के लिये पेंशन देने का प्रावधान भी शामिल है। पेंशन भुगतान पर होने वाला खर्च राज्य सरकार को वहन करना है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में प्रत्येक मृतक के लिये 5 लाख रुपये की बढ़ी हुई राहत राशि प्रदान करने के लिये वर्ष 2014 में एक योजना शुरू की गई। उन्होंने कहा, वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए लोगों के परिजनों को बड़े हुए मुआवजे के भुगतान के लिये 4.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

15 अगस्त से ई-वे बिल सृजित नहीं कर पाएंगे रिटर्न नहीं भरने वाले

-जीएसटीएन ने कहा- इस कदम से अगस्त में जीएसटी संग्रह बढ़ाने में मिलेगी मदद

नई दिल्ली। जीएसटी नेटवर्क में कहा है कि जिन करदाताओं ने जून 2021 तक दो महीने या जून 2021 तिमाही तक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किये हैं, वे 15 अगस्त से ई-वे बिल सृजित नहीं कर पाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से अगस्त में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि लॉबित जीएसटी रिटर्न दाखिल होने की उम्मीद है। पिछले साल केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कोविड महामारी के दौरान अनुपालन राहत देते हुए रिटर्न दाखिल न करने वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ई-वे बिल सृजित करने पर रोक को निलंबित कर दिया था। जीएसटीएन ने करदाताओं से कहा, सरकार ने अब सभी करदाताओं के लिए ईडब्ल्यूबी पोर्टल पर ईवे बिल सृजित करने पर रोक को 15 अगस्त से फिर बहाल करने का फैसला किया है। इस तरह 15 अगस्त 2021 के बाद सिस्टम दाखिल किए गए रिटर्न की जांच करेगा और जरूरी होने पर ईवे बिल सृजित करने पर रोक लगाएगा।

नई दिल्ली, एजेंसियां।

भारत पहली अगस्त को एक महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना है। यूएनएससी की अध्यक्षता संभालने के बाद भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इसका सकारात्मक इस्तेमाल करने को पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को भारत के कार्यकाल में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आयोजित होने वाली एक बैठक की अध्यक्षता करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस महीने हम एक सिग्नेचर डेवेंट आयोजित करेंगे जो तीन अहम क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। ये तीनों क्षेत्र समुद्र की सुरक्षा, शांति अभियान और आतंक के खिलाफ मुहिम से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौ अगस्त

को एक उच्चस्तरीय वर्चुअल ओपन डिबेट की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक का मुद्दा समुद्र की सुरक्षा को लेकर होगा। यह नहीं इसमें अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मसले पर भी चर्चा की जाएगी। अरिंदम बागची ने यह भी बताया कि भारत अफगानिस्तान में विकसित हो रही सुरक्षा स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान के मसले पर शुक्रवार को चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस चर्चा में हम अफगानिस्तान मुद्दे पर अपने विचार और दृष्टिकोण साझा करेंगे। अफगानिस्तान के साथ हमारे घनिष्ठ संबंध हैं जो रणनीतिक साझेदारी समझौते द्वारा निर्देशित हैं। इस समझौते पर दोनों देशों ने 2011 में हस्ताक्षर किए थे। बागची ने कहा कि नौ अगस्त को आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास रचेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब

कोई भारतीय प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारत एक शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और समृद्ध भविष्य के लिए अफगानिस्तान की सरकार और लोगों की आकांक्षाओं को साकार करने का समर्थन कर रहा है। भारत महिलाओं और अल्पसंख्यकों समेत अफगान समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए अफगानिस्तान सरकार का समर्थन कर रहा है। अरिंदम बागची ने पाकिस्तान में हिंदू मंदिर पर हुए हमले को लेकर इमरान सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने पाक के पंजाब प्रांत में रहीम यार खान जिले के भोंग शहर में एक गणेश मंदिर पर हिंसक भीड़ के हमले की सोशल मीडिया पर परेशान करने वाली खबरें देखी हैं। भीड़ ने मंदिर पर हमला किया, पवित्र मूर्तियों को अपवित्र किया



और परिसर में आग लगा दी। भीड़ ने हिंदू समुदाय के आसपास के घरों पर भी हमला किया। पाकिस्तान में पूजा स्थलों पर हमले, अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा,

भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाएं बेरोकटोक जारी हैं। पाकिस्तान की सरकार इन हमलों को रोकने में पूरी तरह विफल रहे हैं।

देश में एक समान शिक्षा पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रावधान

नई दिल्ली।

केंद्र सरकार ने बताया कि देश में एक समान शिक्षा पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में प्रावधान किया गया है, इसके तहत सभी हितधारकों से चर्चा करने के बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) एक नया और व्यापक राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम संबंधी फ्रेमवर्क (एनसीएफएसई) तैयार करेंगी। राज्यसभा में गुरुवार को सवाल के लिखित जवाब में

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने इसकी जानकारी दी। प्रधान ने कहा कि एनसीएफएसई के लिए एक व्यापक रणनीतिक दस्तावेज तैयार किया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘राज्य सरकारों, मंत्रालयों, केंद्र सरकार के संबंधित विभागों और अन्य विशेषज्ञ निकायों सहित सभी हितधारकों से चर्चा करने के बाद एनसीईआरटी द्वारा एक नया और व्यापक एनसीएफएसई के तैयार किए जाने का राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रावधान है। एनसीएफएसई के लिए एक व्यापक कार्यनीति दस्तावेज तैयार किया गया है।’’

प्रधान ने कहा कि राज्य पहले जिला स्तरीय परामर्श प्रक्रिया, मोबाइल एप सर्वेक्षण और एनईपी के अनुसार चिह्नित विषयों में फोकस ग्रुप द्वारा स्थिति पत्र तैयार करने आदि के माध्यम से मौसमी पाठ्यक्रम संबंधी फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। इसमें संबंधित राज्यों के सांस्कृतिक और भौगोलिक स्रोतों को ध्यान में रखा जाएगा। यह पूछे जाने पर कि क्या देश की शिक्षा प्रणाली को कुशल बनाने के लिए सरकार भारतीय शिक्षा सेवा आरंभ कर रही है, प्रधान ने कहा, ‘‘ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।’’

शिलान्यास के प्रथम वर्ष को गांठ अयोध्या में उल्लास के साथ मिलाईयां बांटकर उत्सव मनाया गया

अयोध्या।

500 वर्षों के मंदिर निर्माण का इंतजार अब समाप्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस लेकुर चारों तरफ खुशी का माहौल है। गुरुवार के दिन राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए शिलान्यास के प्रथम वर्ष को गांठ को अयोध्या में उल्लास के साथ मिलाईयां बांट कर उत्सव मना रहे हैं। 5 अगस्त 2020 में राम मंदिर की नींव रखने के एक वर्ष पूरे हुए हैं, इस लेकर तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने सुबह संतो

के साथ भगवान श्री राम की आरती उतारी और मिठाईयां बांटकर खुशियां मनाई। इस दौरान चालीसा जय श्री राम के जमकर नारे लगाए। वहीं कई राज्यों से अयोध्या पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ता भी हनुमान गढ़ी सहित अन्य मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। महंत परमहंस दास ने बताया कि आज 5 अगस्त सांस्कृतिक आजादी के रूप में मना रहे हैं। क्योंकि 500 वर्षों के



लंबे संघर्ष के बाद हमारी कितनी पीढ़ियां चल गईं। लाखों रामभक्तों को अपने प्राणों को आहुत कर दिए। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय से राम मंदिर के पक्ष में जो फैसला आया और देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भूमि पूजन हुआ।

हंगामे के बीच रास में तीन विधेयक संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित

-गुरुवार को भी होता रहा विपक्ष का हंगामा, चार बार के स्थगन के बाद रास स्थगित

नई दिल्ली।

पेगासस जासूसी विवाद तथा तीन कृषि कानूनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक गुरुवार को चार बार के स्थगन के बाद अपराह्न चार बज कर दस मिनट पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच सदन में तीन विधेयकों को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित किया गया। पूर्वाह्न 11 बजे के बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने तृणमूल की एक सदस्य के एक दिन पहले के आचरण को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उसकी निंदा की। उपसभापति ने कहा कि अशोभनीय व्यवहार के कारण तृणमूल कांग्रेस के छह सदस्यों को एक दिन के

लिए सदन से निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि कल जब सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित हो गयी तो निलंबित सदस्यों में से एक ने सदन में प्रवेश करने की कोशिश की। इस क्रम में एक द्वार का शीशा टूट गया और एक महिला सुरक्षा अधिकारी को चोट भी आयी। उस अधिकारी ने इसकी शिकायत दर्ज करायी है और सभापति एम वेंकैया नायडू इस पर विचार कर रहे हैं। इस घटना को लेकर तृणमूल कांग्रेस के सुखेंद्र शेखर राय ने कहा कि लगाए गए आरोप सही नहीं हैं क्योंकि उनकी पार्टी के सदस्यों को दिन भर के लिए सदन से निलंबित किया गया था और बैठक जब स्थगित की गई तब सदस्य सदन में छूट गए अपने बैग को लेने के लिए अंदर आना चाह रही थीं। इसी प्रक्रिया में द्वार में लगा शीशा टूटा। उन्होंने कहा

जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश करने का आरोप सही नहीं है। दरवाजा बंद कर उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि सदस्य को अंदर आने से रोकने के लिए दरवाजा बंद नहीं किया गया था बल्कि नियमित प्रक्रिया के तहत, सैनटाइजेशन के लिए दरवाजा बंद किया जा रहा था। गोयल ने कहा कि नियमित कार्य में किसी को बाधा नहीं डालनी चाहिए और इस तरह के आचरण से कर्मचारियों को मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिवंगत पूर्व नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली के उस बयान की ओर सदन को ध्यान दिलवाया कि बाधा डालना लोकतंत्र का एक अंग होता है। उन्होंने कहा कि कल की घटना नयी नहीं है। उन्होंने कहा हम अपनी बात रखने के लिए जो कुछ भी करते हैं वह

लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं। खड़गे की इस बात पर सत्तापक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताई। सदन में व्यवस्था बनते न देख हरिवंश ने 11 बज कर 15 मिनट पर बैठक को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। उच्च सदन की बैठक 15 मिनट बाद पुनः शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य फिर आसन के समक्ष आ कर हंगामा करने लगे। पीठासीन अध्यक्ष भुवनेश्वर कालिता ने हंगामा थमते न देख बैठक को दोपहर बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। बारह बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा। विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा कि जब सदन की कार्यवाही स्थगित की गयी, उस समय वह अपनी बात रख रहे थे लेकिन उनकी बात पूरी भी नहीं हुयी थी। इस पर उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सदन में हंगामा आप देख रहे हैं और इसी वजह

से कार्यवाही स्थगित की गयी थी। खड़गे ने कहा कि हंगामा में विधेयक पारित हो सकता है लेकिन उनकी बात पूरी नहीं हो सकती। राज्यसभा में भाजपा के उप नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिये आयोग उन्होंने कहा कि आपत्ति हिंसा, तोड़फोड़ और हाथपाई को लेकर है। इसके बाद उपसभापति ने हंगामे के बीच ही कार्यवाही 12 बजकर करीब 20 मिनट पर दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी। दोपहर दो बजे जब उच्च सदन की बैठक पुनः आरंभ हुई तब विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही तीन

विधेयकों को ध्वनिमत से पहले संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2021 को सदन में ध्वनिमत से पारित किया गया। फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिये आयोग विधेयक, 2021 तथा फिर अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को ध्वनिमत से मंजूरी दी गई। ये दोनों विधेयक लोकसभा में पारित हो चुके हैं। जब अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक पर चर्चा शुरू हुई तब हंगामे के बीच इसमें अपनी बात रख रहे सदस्यों ने कहा कि यह विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। कई सदस्यों ने विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने की मांग भी की। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जिस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग विपक्ष 14

दिन से कर रहा है, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है और इस विधेयक पर चर्चा कराई जा रही है जो आज की कार्यसूची में शामिल नहीं था। इसे प्रवर समिति में भेजा जाना चाहिए। खड़गे के इतना कहते ही सदन में हंगामा तेज हो गया और पीठसीन अध्यक्ष भुवनेश्वर कालिता ने सदन की कार्यवाही तीन बजकर करीब 10 मिनट पर आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी। तीन बज कर 40 मिनट पर बैठक पुनः शुरू हुई तब अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को ध्वनिमत से मंजूरी दी गई। इस विधेयक के पारित होने के बाद उप सभापति हरिवंश ने चार बज कर करीब दस मिनट पर बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले उच्च सदन की बैठक हंगामे के कारण ही दो बार स्थगित की गई थी।

संपादकीय

स्वभाषाओं का स्वागत लेकिन.... ?

(लेखक- डॉ. वेदप्रताप वैदिक)

यह खुश खबर है कि देश के आठ राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कालेजों में अब पढ़ाई का माध्यम उनकी अपनी भाषाएँ होंगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ पर इस क्रांतिकारी कदम का कौन स्वागत नहीं करेगा? अब बी टेक की परीक्षाओं में छात्रागण हिंदी,मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, बांग्ला, असमिया, पंजाबी और उड़िया माध्यम से इंजीनियरी की शिक्षा ले सकेंगे। मातृभाषा के माध्यम का यह शुभ-कार्य यदि 1947 में ही शुरु हो जाता और इसे कानून, गणित, विज्ञान, चिकित्सा आदि सभी पाठ्यक्रमों पर लागू कर दिया जाता तो इन सात दशकों में भारत विश्व की महाशक्ति बन जाता और उसकी संपन्नता यूरोप के बराबर हो जाती। दुनिया का कोई भी शक्तिशाली और संपन्न देश ऐसा नहीं है, जहाँ विदेशी भाषा के माध्यम से पढ़ाई होती हो। हिरन पर घांस लाने की मूर्खता सिर्फ भारत-जैसे पूर्व गुलाम देशों में ही होती है। इसके विरुद्ध डॉ. लोहिया ने जो स्वभाषा आंदोलन चलाया था, उसका मूर्त रूप अब देखने में आ रहा है। जब 1965-66 में मैंने इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में अपना पीएच.डी. का शोध ग्रंथ हिंदी में लिखने की मांग की थी तो मुझे निकाल बाहर किया गया था। संसद ठप हो गई थी लेकिन उसके 50-55 साल बाद अब क्रांतिकारी कदम उठाने का साहस भाजपा सरकार कर रही है। सरकार में दम और दृष्टि हो तो शिक्षा में से अंग्रेजी की अनिवार्य पढ़ाई पर कल से ही प्रतिबंध लगाए और देश के हर बच्चे को पढ़ाई उसकी मातृभाषा में ही हो। अंग्रेजी समेत कई अन्य विदेशी भाषाएँ स्वेच्छया पढ़ाने की सुविधाएँ विश्वविद्यालय स्तर पर जरूर हों लेकिन यदि शेष सारी पढ़ाई स्वभाषा के माध्यम से होगी तो यह निश्चित जानिए कि नौकरियों में आरक्षण अपने आप अनावश्यक हो जाएगा। गरीबों, ग्रामीणों और पिछड़ों के बच्चे बेहतर सिद्ध होंगे। परीक्षाओं में फेल होसवालों की संख्या घट जाएगी। कम समय में ज्यादा पढ़ाई होगी। पढ़ाई से मुख मोड़नेवाले छात्रों की संख्या घटेगी। छात्रों की मौलिकता बढ़ेगी। वे नए-नए अनुसंधान जल्दी-जल्दी करेंगे। लेकिन भारत की शिक्षा का स्वभाषाकरण करने के लिए सरकार में अदम्य इच्छा-शक्ति की जरूरत है। रातों-रात दर्जनों पाठ्य-पुस्तकें, संदर्भ-ग्रंथ, शब्द-कोश, प्रशिक्षण शालाएँ आदि तैयार करवाने का जिम्मा शिक्षा मंत्रालय को लेना होगा। स्वभाषा में शिक्षण का यह क्रांतिकारी कार्यक्रम तभी अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा, जब सरकारी नौकरियों से अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त होगी। क्या किसी नेता या सरकार में दम है, यह कदम उठाने का? यदि आपने संसद में, अदालतों में, सरकारी काम-काज में और नौकरियों में अंग्रेजी को महारानी बनाए रखा तो मातृभाषाओं की हालत नौकरानियों-जैसी ही बनी रहेगी। मातृभाषाओं को आप पढ़ाई का माध्यम जरूर बना देंगे लेकिन उस माध्यम को कौन अपनाना चाहेगा?



‘आज के ट्वीट

जीत

जीतने वाले कुछ अलग चीज़े नहीं करते, बस वो चीज़ो को अलग तरीके से करते हैं !!

-- विवेक बिन्दा

ज्ञान गंगा

सद्गुरु

अगर तलाश के लिहाज से, अनुभव करने और जानने के लिहाज से बात की जाए, तो आत्मज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है। खोज करने के लिए वाकई कुछ और नहीं है। लेकिन अगर जीवन जीने के लिहाज से बात की जाए तो उसके अलावा भी बहुत कुछ है। देखिए जीवन के आखिरी पलों में जब आपकी सांसें डूब रही होंगी, उस समय आपको आत्म-ज्ञान कराना मेरे लिए बच्चों का खेल होगा। क्योंकि उन क्षणों में आप बेहद संवेदनशील और ग्रहणशील हो जाते हैं। तब आपको आसानी से बदला जा सकता है। लेकिन अभी मैं आपसे कुछ भी कहता हूँ तो कुछ देर बाद आप एक नये तर्क के साथ मेरे पास आ जाते हैं। मैं चाहे आपके साथ कुछ भी करूँ, मैं आपको चाहे जैसे अनुभव कराऊँ, लेकिन आप दो महीने बाद वापस आ जाएंगे और मुझसे पूछेंगे कि ‘यह क्या है?’ लेकिन फिलहाल हम आपको जीवन नहीं लेना चाहते, इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं। हम बस आपके मरने का इंतजार कर रहे हैं। या फिर हम इसका इंतजार कर रहे हैं कि आप अपने सिस्टम

आत्म-ज्ञान

पर पूरी महारत हासिल करें, ताकि आप आत्म-ज्ञानी हो जाएँ और साथ ही इस शरीर में भी रह सकें। आत्मज्ञान सरल है, यह परम प्रक्रिया है, लेकिन अपने आप में आसान है। कहा भी गया है- ‘आत्मज्ञान अति सुलभम्। आत्म-ज्ञान पाना बहुत आसान है, लेकिन अपने इस शरीर को थामे रखने की तकनीक काफी जटिल है। इसके लिए जबरदस्त समझ, जुड़ाव, प्रज्ञा और साधना की जरूरत होती है। चलिए हम इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए हमने आपके लिए फरारी का इंतजाम किया। आप पहले से ही कार चलाना जानते हैं, अभी तक आप मारुति कार चला रहे थे। फरारी में जिस तरह की शक्ति होती है, उसके चलते हो सकता है कि शुरु में यह आपको थोड़ा बहुत नचाए व परेशान करे, लेकिन एक दिन में या फिर कुछ घंटों में आपको फरारी समझ में आने लगती है और तब आप इसे दौड़ाने लगते हैं। लेकिन अब आप चाहते हैं कि हर व्यक्ति के पास एक फरारी हो। अब आप अपने गांव में फरारी बनाना चाहते हैं। इसमें एक बिन्दुलु अलग तरह की भागीदारी की जरूरत होगी। तो केवल उस संदर्भ में मैंने कहा कि अगर आपको आत्म-ज्ञान की तलाश है तो आप इंतजार कीजिए।

बाढ़ के समक्ष बौनी और असहाय क्यों है हमारी व्यवस्था?



(लेखक- योगेश कुमार गोयल)

इस साल भी प्रतिवर्ष की भांति बिहार सहित देश के कई राज्य बाढ़ के कहर से त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। इन राज्यों के हालातों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है, जैसे मानसून के दौरान बाढ़ के कहर को झेलना अब लोगों की नियति बन गया है, जिसे लेकर इन राज्यों के नीति नियंत्रणों की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्वतीय क्षेत्रों में बीते कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से विभिन्न नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जिससे उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश के कई तटीय इलाके भी बाढ़ की आशंका से सहमे हैं और कुछ इलाके तो जलमग्न भी हो चुके हैं। यह बेहद चिंताजनक स्थिति है कि देशभर में अनेक राज्यों में हर साल कुछ घंटों की लगातार बारिश से ही नदियाँ और बरसाती नालों में उफान आ जाता है, यहां तक कि देश की राजधानी दिल्ली में भी चंद घंटों की बारिश से ही बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, महाराष्ट्र, झारखण्ड इत्यादि कई राज्य इन दिनों जल-प्रलय से जूझ रहे हैं। अनेक इलाकों में तो बाढ़ के कारण

सड़कों पर आवागमन पूरी तरह ठप है। हालात ऐसे हैं कि बिहार के कई इलाकों में तो बाढ़ के कारण सड़कों पर ही नाव चल रही है। ग्रामीण आबादी तो बाढ़ के कहर से जूझ ही रही है, शहरी इलाकों की बड़ी आबादी भी इससे परेशान है। बिहार में तो नदियाँ पूरे उफान पर हैं और भारी बारिश तथा नेपाल से आने वाली नदियों में उफान से उत्तर बिहार के अलावा कोसी, सीमांचल तथा पूर्वी बिहार में स्थिति निरन्तर गंभीर हो रही है

लेकिन बिहार प्रशासन दावा करता रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है। बाढ़ की बेकाबू होती स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राज्य के हजारों गांव बाढ़ के पानी से लबाबत हैं। बाढ़ ने बिहार के 10 जिलों के करीब 60 प्रखण्डों में जमकर कहर बरपाया है और आने वाले दिनों में भारी बारिश के कारण हालात और बदतर हो सकते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक बाढ़ के कारण अब तक कई दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है और 80 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, सैकड़ों जानवर बाढ़ के पानी में बह चुके हैं। कोविड काल में वैक्सिनेशन के लिए बिहार सरकार द्वारा ‘टीका वाली नाव’ तो चलाई गई हैं लेकिन हर साल इसी प्रकार बाढ़ का कहर झेलने को अभिशप्त बिहार की जनता के लिए इस साल भी सरकार द्वारा ऐसे कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिससे मानसून की शुरुआत होते ही ऐसी परिस्थितियां निर्मित ही नहीं होती। 2019 में तो बिहार में दरभंगा और मधुबनी में कमला बाढ़ बांध दर्जनों जगहों से टूट जाने के चलते हालात बाढ़ से बदतर हो गए थे। जगह-जगह तटबंधों में बड़ी-बड़ी



गुस्से के वक़्त थोड़ा रुक जाने से, और गलती के वक़्त थोड़ा झुक जाने से, जिन्दगी आसान हो जाती है!

(लेखक-ऋतुपर्ण देव)

जहां बारिश ने फ़िलाहाल दुनिया भर में जगह-जगह न केवल पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए वहीं बेतहाशा गर्मी ने भी तमाम जगह तबाही मचाकर भविष्य के लिए बुरे संकेत भी दे दिए। बावजूद इसके इसानी करतूतों में बदलाव नहीं आना ठीक वैसा ही जैसे आ बैल मुझे मार! मौजूदा ऑकड़ें और पुराने दरतावेज बताते हैं कि सूखा और बारिश सृष्टि की रचना के साथ ही प्रकृति के अभिन्न हिस्से जरूर रहे हैं और कहीं बारिश की तबाही तो कहीं सूखे की मार का जिक्र इतिहासों के पुराने पन्नों में भी दर्ज है। लेकिन ऐसा खौफनाक मंजर धरती के इतने बड़े भूभाग पर एक साथ इस कदर दिखा हो याद नहीं आता। सभी को प्रकृति के उन इशारों को समझना होगा, चेतना होगा और रू-ब-रू होकर दूरियां बनानी होगी जो मौजूदा हालातों के लिए जिम्मेदार हैं। बीते बरस प्राकृतिक आपदाओं के कारण दुनिया भर में बेघर हुए लोगों की संख्या 10 बरसों में सबसे ज्यादा रही। जहां साढ़े 5 करोड़ लोग अपने ही देशों में विस्थापित हुए वहीं ढाई करोड़ से ज्यादा दूसरे देशों में शरणगत हुए। चीन के हेनान में एक हजार साल के रिकॉर्ड में पहली बार इतनी बारिश हुई कि बड़ी संख्या में लोग मारे गए, सड़कों पर हफ्तों पानी भरा रहा। यूरोप में दो दिन में ही इतना पानी बरसा जितना दो महीने में बरसता है। नदियों के तट टूट गए। पानी गांवों और शहरों में जा घुस और हजारों घर, दुकान, दफ्तर, अस्पताल सब पानी-पानी हो गए। जर्मनी और बेल्जियम में सैकड़ों मौतें हो गईं। सदियों पुराने बसे और आबाद गांव एक ही रात में बह गए। भारत में भी महाराष्ट्र, उग्र, उत्तराखण्ड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, मप्र, बिहार, झारखण्ड प.बंगाल, सहित दक्षिणी राज्यों कुल मिलाकर पूरे देश का काफी बुरा हाल है। हर कहीं बारिश की तबाही की नई और खौफनाक तस्वीरें काफी डराती हैं। तबाही की वजह केवल बारिश और बाढ़ ही हो ऐसा नहीं है। अमेरिका के वाशिंगटन और कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में हीट डोम बनने के चलते हवा एक जगह फंसी रह गई जिससे तापमान 49.6 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। वहीं अमेरिका के अरिज़न के जंगल में लगी आग ने दो हफ्ते में ही लॉस एंजेलसे जितना इलाका जलाकर राख कर दिया। अंदाजा ही काफी है कि पर्यावरण को कितना जबरदस्त नुकसान हुआ होगा। बरसों बरस रहे रहे-भरे जंगल का क्षेत्र वीरान रेगिस्तान में तब्दील हो गया। इतनी ही नहीं यहां के सुलगते जंगलों की जलती लकड़ी का धुआ न्युयार्क के लोगों की सांसों पर अलग भारी पड़ रहा है। ब्राजील का मध्यवर्ती इलाका शताब्दी का सबसे बुरा सूखा झेल रहा है। जंगलों की आग से जहां चारों ओर खतरा तो बढ़ा ही वहीं अब अमेजन के जंगलों पर भी अस्तित्व समाप्ति का संकेत सामने है। इतना तो पता है जो भी कुछ हो रहा है महज जलवायु पर संकट के चलते हो रहे परिवर्तन के कारण ही है। आखिर जलवायु परिवर्तन है क्या? यह समझना अभी भी कई लोगों के लिए थोड़ा आसान नहीं है। बिना लाग लपेट इसे इस तरह समझा जा सकता है कि दुनिया में औद्योगिक क्रान्ति की शुरुआत 1850 से 1900 के बीच हुई। उस वक्त धरती का जितना तापमान था उसे ही मानक इकाई मानकर स्थिर रखना है ताकि पर्यावरण भी स्थिर रहे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। जिस तरह से पर्यावरण

को ताक में रखकर बेतहाशा प्रदूषण फैलाया गया उससे पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ रहा है जो जल्द ही 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। बस यही बढ़ता तापमान प्रकृति की सेहत पर बुरी तरह से भारी पड़ रहा है। बारिश और गर्मी के चलते हो रही प्राकृतिक आपदाओं की वजह भी यही तापमान वृद्धि है। इसे काबू में रखने की कवायद पूरी दुनिया को ईमानदारी से करनी होगी। हालांकि यह वृद्धि सरसरी तौर पर तो मामूली लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग 98.6 डिग्री फ़ैरेनहाइट यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जिसके थोड़ा ही बढ़ते तबियत खराब लगने लगती है, शरीर असहज लगने लगता है और 101-102 डिग्री फ़ैरेनहाइट होते-होते शारीरिक क्षमताएं बुरी तरह से असामान्य होने लगती हैं। तमाम व्याधियां व पीड़ाएं घेर लेती हैं। ठीक वैसा ही पृथ्वी के साथ है। इसलिए पूरी दुनिया का ध्यान इसी 1.5 डिग्री सेल्सियस को बढ़ने से पहले ही नियंत्रित कर लेने पर है। औद्योगिकीकरण व शहरीकरण के चलते ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाईऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हैलोकार्बन आदि ही जलवायु परिवर्तन के कारण हैं। इनसे वायुमंडल का तापमान लगातार बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसों की भूमिका भी खास है जो इसान की देन है। आंकड़े बताते हैं कि 10 बरसों में दुनिया भर में जीवाश्म ईंधन यानी लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व जीवों के जल कर उच्च दाब और ताप में दबने से बना प्राकृतिक ईंधन जो अब कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि के रूप में है, भी बड़ा कारण है। इनका उपयोग बिजली घरों, वाहन चलाने, खाना पकाने, रोशनी फैलाने में किया जाता है जो बड़े पैमाने पर वायुमण्डल में रोजाना और हर पल प्रदूषण फैलाता है और धरती का तापमान बढ़ाता है। जीवाश्म ईंधन व दूसरी औद्योगिक प्रक्रियाओं के कारण दुनिया भर में कार्बन डाईऑक्साइड के उत्सर्जन में 4,578.35 मिलियन मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। इससे वायुमंडल गर्म हो रहा है और यही ग्लोबल वॉर्मिंग का कारण है। यही जलस्रोत, ग्लेशियर, जैव विविधता के साथ कृषि उत्पादकता और मानव जीवन प्रभावित कर रहा है। धरती पर तापमान बढ़ने का सिलसिला ऐसा ही रहा तो सन् 2030 से 2052 तक धरती के तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। जो कहीं न कहीं पृथ्वी के पर्यावरण पर अत्याधिक प्रतिकूल होगा। शोधकर्ताओं के अनुसार वाहनों और उद्योगों से निकलने वाले कार्बन डाईऑक्साइड से पादप और फंफूदी के पराग, बीजाणु के उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। यही हवा के माध्यम से मानव शरीर में पहुंच कर अस्थमा, राइनइटिस, सीओपीडी, स्किन कैंसर एवं अन्य एलर्जी जैसे घातक बीमारियों को जन्म देते हैं। ग्रीन हाउस गैसों कितनी घातक हैं समझा जा सकता है। इसको लेकर दुनिया भर में लगातार बैठकें और विचार विमर्श होता रहता है। बावजूद इसके कुछ खास हासिल नहीं हो सका। अब इस दिशा में आशा की एक किरण जरूर दिख रही है। वह है जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल यानी इंटरगवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी)। इसकी स्थापना विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण



कार्यक्रम ने 1988 में की थी जो जलवायु के बारे में मूल्यांकन कर कुछ सालों के अंतराल पर रिपोर्ट जारी करता है। यह रिपोर्ट बेहद आसान भाषा में होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे पढ़ सकें और जागरूक हो सकें। इसका काम कितना महत्वपूर्ण है इसी से समझा जा सकता है कि वर्ष 2007 में संस्था शांति नोबल पुरस्कार से सम्मानित की गई। इसमें दुनिया भर के चुने हुए वैज्ञानिक काम करते हैं जो विशेषज्ञ वैज्ञानिकों, सरकारों और उद्योग जगत के तमाम दावों व रिपोर्ट्स का बारीक अध्ययन कर जलवायु परिवर्तन की स्थितियों, कारणों पर नए व तथ्यात्मक शोध व प्रमाणित लेखों का विश्लेषण कर अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं। आईपीसीसी के वैज्ञानिक सरकारों को नहीं बताते कि क्या करना है बल्कि नीतिगत विकल्प का आकलन करते हैं। ये भविष्यवाणी नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन के चलते हो चुकी घटनाओं पर रिपोर्ट से पहले अमला अनुमान जारी करते हैं जिसकी संयुक्त राष्ट्र समीक्षा रिपोर्ट 2014 में जारी हुई थी जिस पर 2015 के पेरिस समझौते में तय हुआ कि इस शताब्दी के अंत तक ग्लोबल वॉर्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखना है। छठवीं रिपोर्ट के ड्राफ्ट की समीक्षा जारी है जो इसी पखवाड़े किसी भी दिन जारी होगी। इसी नवंबर में ग्लासगो में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP26) में इससे जुड़े फैसलों की घोषणा की जाएगी।

जिसके मूल्यांकन से जुड़ी पूरी रिपोर्ट 2022 में जारी होगी। यही वक्त है जब जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया के हरेक नागरिक को चेतना होगा, जागरूक होना होगा। यह बहुत ही कठिन है। लेकिन जब तक सारी दुनिया ग्लोबल वॉर्मिंग के दिख रहे दुष्परिणामों को लेकर सचेत नहीं होगी, समझेगी नहीं धरती का तापमान यूं ही बढ़ता रहेगा और खामियाजा मौजूदा हालातों से भी बदतर होगा। काश समय रहते लोग इसे समझ पाते और आईपीसीसी की मंशा सार्थक हो पाती। मेरा प्रदूषण-तेरा प्रदूषण को लेकर यूं ही मरी खींचतान के बीच धरती का तापमान यानी बुखार बढ़ता रहेगा उसके पसीने की बाढ़ या तू के थपड़े प्रकृति के जीव-जन्तुओं पर ऐसे भारी पड़ेंगे मानों अगले करोड़ों वर्षों के लिए हम जीवाश्म ईंधन बन जितना दोहन कर चुके हैं उसकी भरपाई का जरिया न बन जाए! ‘धरती कहे पुकार के मत रौंदे तू मोय वरना वो दिन आएगा मैं रौंदूंगी तोय।’ काश इसे समझ पाते?

आज का राशिफल

मे़ष गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कार्यक्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च करने के योग हैं। राजनैतिक दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे।

वृषभ पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। रुपए पैसे के लेन-देन में सावधानी रखें। आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें।

मिथुन आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। प्रेम प्रसंग प्रगाढ़ होंगे। किसी अभिन्न मित्र या रिश्तेदार से मिलाप की संभावना है।

कर्क बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। पारिवारिक जनों से पीड़ा मिलने के योग हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। प्रणय संबंध मधुर होंगे।

सिंह व्यावसायिक योजना सफल होगी। आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। मकान सम्पत्ति व वाहन की दिशा में किया गया प्रयास सफल होगा।

कन्या रोजी रोजगार की दिशा में सफलता के योग हैं। सृजनात्मक कार्यों में हिस्सा लेना पड़ सकता है। खान-पान में संयम रखें। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। दूसरों से सहयोग लेने में सफल रहेंगे।

तुला शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। अपनों का सहयोग मिलेगा। वाणी की सौम्यता आपको कल लाभ करायेंगी। व्यर्थ की भागदौड़ होगी।

वृश्चिक व्यावसायिक योजना सफल होगी। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें। आर्थिक उन्नति होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।

धनु पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। व्यावसायिक योजना सफल होगी। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा।

मकर बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। नेत्र विकार की संभावना है। अनावश्यक व्यय का सामना पड़ेगा।

कुम्भ दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। खान-पान संयम रखें। आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे। विरोधियों का पराभव होगा।

मीन जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। संतान के कारण चिंतित रहेंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। प्रेम प्रसंग प्रगाढ़ होंगे। रुका हुआ कार्य सम्पन्न होगा।



रुपये में तेजी बरकरार

मुंबई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में गुरुवार को भारतीय रुपये में तेजी आई है। अंतरबैंक विदेशीमुद्रा विनिमय बाजार में रुपया दो पैसे की मामूली तेजी के साथ ही 74.17 रुपये पर बंद हुआ। निवेशकों को अब भारतीय रिजर्व बैंक के शुक्रवार को होने वाले नीतिगत फैसलों का इंतजार है, जिससे कारोबारी गतिविधियों में कमी दिखी। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में सुबह रुपया 74.15 पर खुला तथा कारोबार के दौरान 74.28 रुपये के निम्नतम स्तर तक पहुंच गया। अंत में यह पिछले सत्र के बंद भाव के मुकाबले दो पैसे की तेजी के साथ 74.17 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। इससे पहले रुपया 74.19 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.05 फीसदी की गिरावट के साथ ही 92.22 रह गया।

कोवैक्सीन को हंगरी में जीएमपी

प्रमाणपत्र

हैदराबाद। भारत बायोटेक के कोरोना वायरस के टीके को हंगरी में गुड मैनुफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जीएमपी) अनुपालन प्रमाणपत्र मिला है। टीका विनिर्माता ने टिवटर पर यह जानकारी दी। कंपनी ने एक ट्वीट में कहा कि हमने एक और मुकाम प्राप्त कर लिया है। कोवैक्सीन को हंगरी में जीएमपी प्रमाणपत्र दिया गया। यह यूरोपीय नियामकों से भारत बायोटेक को मिला पहला यू.इ.ए.जी.डी.एम.पी अनुपालन प्रमाणपत्र है। टिवटर पर डाले गए एक नोट में कहा गया कि हंगरी के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मासी एंड न्यूट्रिशन ने कोवैक्सीन के विनिर्माण के लिए जीएमपी प्रमाणपत्र दिया है। भारत बायोटेक ने कहा कि जीएमपी प्रमाण पत्र अब यू.इ.ए.जी.एम.डी.पी डेटाबेस में सूचीबद्ध है जो विनिर्माण प्राधिकरणों के यूरोपीय समुदाय के रिकॉर्ड और अच्छे विनिर्माण अभ्यास के प्रमाण पत्र का संग्रह है।

स्पाइसजेट और गो फर्स्ट ने नहीं किया

2.74 करोड़ का भुगतान

नई दिल्ली । विमानन कंपनी स्पाइसजेट और गो फर्स्ट ने एक जून तक अहमदाबाद हवाई अड्डे के रनवे का उपयोग करने के लिए लगभग 2.74 करोड़ रुपए बकाये का भुगतान नहीं किया है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने यह जानकारी दी है। गो फर्स्ट को पहले गोएयर के नाम से जाना जाता था। कोरोना वायरस महामारी के बीच मार्च 2020 से यात्रा प्रतिबंधों के कारण एयरलाइन को भारी नुकसान हुआ है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सिंह ने कहा कि पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान अहमदाबाद हवाई अड्डे के रनवे का उपयोग करने वाली निजी कंपनियों की संख्या, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेटर भी शामिल हैं, 500 है।

सरकार ने बांधों में सुधार के लिए

विश्वबैंक से किया ऋण समझौता

नई दिल्ली। सरकार ने कहा कि उसने विश्व बैंक के साथ 25 करोड़ डॉलर (लगभग 1,855 करोड़ रुपए का) ऋण समझौता किया है और इस राशि का इस्तेमाल देश में मौजूदा बांध ढांचे को सुरक्षित बनाने में किया जाएगा। केंद्रीय जल आयोग के साथ 10 हिस्सेदार राज्यों के सरकारी प्रतिनिधि भी ऋण समझौते का हिस्सा हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि समझौते के मौके पर 10 राज्यों छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान और तमिलनाडु और केंद्रीय जल आयोग ने भाग लिया। जानकारी के मुता बिक लंबी अवधि की यह 25 करोड़ डॉलर की परिधिना बांध सुरक्षा कार्यक्रम और भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूदा बांधों की सुरक्षा एवं प्रदर्शन में सुधार के लिए है।

बिड़ला के चेयरमैन पद से हटने के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयरों में जारी गिरावट

मुंबई।

कुमार मंगलम बिड़ला के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के पद से हटने के बाद गुरुवार को वोडाफोन आइडिया के शेयरों में और गिरावट देखी गई है। बिड़ला ने कंपनी को चालू रखने के लिए कर्ज में डूबी कं.पनी को अपनी हिस्सेदारी सरकारी संस्थाओं को सौंपने की पेशकश के बाद पिछले तीन दिनों से इसके शेयरों में गिरावट दर्ज की है। सुबह करीब 11.50 बजे, बीएसई पर इसके शेयर 5.33 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जो इसके पिछले बंद से 11.61

प्रतिशत कम है। इसने 4.55 रुपये प्रति शेयर के नए 52 सप्ताह के निचले स्तर को छुआ। बुधवार को एक नियामक फाइलिंग में, कंपनी ने कहा, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल ने आज हुई अपनी बैठक में कुमार मंगलम बिड़ला के गैर-कार्यकारी निदेशक और गैर- कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। बोर्ड 4 अगस्त, 2021 को कार्य समय की समाप्ति की वजह से यह प्रभाव है।नतीजतन, बोर्ड ने सर्वसम्मति से हिमांशु कपानिया, जो वर्तमान में एक गैर-कार्यकारी



वित्तीय स्थिति में है, एजीआर बकाया राशि में 50,399.63 करोड़ रुपये है। यह पहले ही 7,854.37 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है।

है - जो इसके दीर्घकालिक औसत से 79 प्रतिशत से ऊपर है।निफ्टी 12 महीने के फॉरवर्ड रिटर्न ऑन इंडिटी (आरओई) पर 14.9 फीसदी के अपने दीर्घकालिक औसत से ऊपर कारोबार कर रहा है।अमेरिका, इंडोनेशिया और भारत को छोड़कर, जुलाई 2021 में चीन, जापान, ब्राजील, कोरिया, ताइवान, रूस और यूक्रे जैसे प्रमुख वैश्विक बाजारों और अन्य उभरते बाजारों में स्थानीय मुद्रा की दृष्टि से गिरावट देखी गई। भारतीय शेयर वित्त वर्ष 22 की आय के 21.7 गुना पर कारोबार कर रहे हैं। अमेरिका प्रीमियम पर एकमात्र बाजार व्यापार है, जबकि अन्य प्रमुख बाजार भारत के मुकाबले छूट पर व्यापार करना जारी रखते हैं।

शेयर बाजार में तेजी बरकरार



सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद मुंबई ।

मुम्बई शेयर बाजार में गुरुवार को भी तेजी बनी रही हालांकि कारोबार के दौरान उतार-

आरबीआई ने चालू खातों के नए नियमों की समयसीमा बढ़ाई

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों के लिए चालू खातों के नए नियमों को लागू करने की तारीख बढ़कार 31 अक्टूबर कर दी है। पिछले कुछ दिनों में छोटे कारोबारियों के चालू खाते बंद किए जाने से उनके कारोबार पर पड़ रहे असर से जुड़ी विभिन्न रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया है। आरबीआई ने कहा कि चालू खाते के लिए नए नियमों का उद्देश्य कर्जदारों के बीच ऋण अनुशासन लागू करने के साथ-साथ बैंकों को बेहतर निगरानी की सुविधा प्रदान करना है। उसने हालांकि नए चालू खाते और नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट सीसी/ओडी सुविधाओं के मामले में बैंकों से सतर्क रह अपनाने को कहा है। आरबीआई ने कहा कि बैंकों को इन निर्देशों को उधारकर्ताओं की वास्तविक व्यावसायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बिना किसी बाधा के लागू करने की जरूरत थी। उसने कहा कि पिछले कुछ दिनों में उसे छोटे कारोबारियों से बैंक द्वारा उनके खाते बंद किए जाने की शिकायतें मिली हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा कि नए नियमों को लागू करने संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए उसे बैंकों से कुछ और समय के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। जिसके चलते नियमों को लागू करने की समयसीमा को बढ़ाकर 31 अक्टूबर, कर दिया गया है।



टेक्नो की पोवा 2 पहली सेल 10499 रुपये की आकर्षक कीमत पर अमेजॉन पर लाइव

नई दिल्ली।

वैश्विक स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो ने 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को और अधिक आनंदमय बनाने के उद्देश्य से, गुरुवार को सीमित समय अवधि के लिए ब्रांड के कुछ लोकप्रिय स्मार्टफोन्स पर रोमांचक छूट और ऑफर्स की घोषणा की, जिसमें अमेजॉन पर पोवा 2 की शुरुआत भी शामिल है। पोवा 2 पांच से नौ अगस्त से अमेजॉन के ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल पर दो स्टोरेज वेरिएंट में 4 जीबी प्लस 64 जीबी के लिए 10,499 रुपये और 6 जीबी प्लस 128 जीबी के लिए 12,499 रुपये के विशेष लॉन्च मूल्य पर उपलब्ध है। कंपनी ने एक बयान में कहा, वर्तमान में, पोवा 2 एकमात्र स्मार्टफोन है, जिसमें 7000 एमएचएच की बैटरी 15 हजार से कम की श्रेणी (सेगमेंट) में उपलब्ध है। कंपनी ने कहा, यह 48 मेगापिक्सल एआई क्राइ-कैमरा सेट-अप, मीडियाटेक हीलियो

जी85 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, 18वॉट ड्यूल आईसी फास्ट चार्ज और 6.95 एचएचडी प्लस डॉट-इन डिस्प्ले और बेहतरीन वीडियो और गेम स्ट्रीमिंग अनुभव जैसी अविश्वसनीय सुविधाओं की पेशकश करने के साथ एक सम्मोहक पावर-पैक प्रदर्शन पैकेज बन जाता है। तकनीक की समझ रखने वाले मिलेनियल और जेन जेड उपभोक्ताओं के लिए डिज़ाइन किया गया पोवा 2 स्मार्टफोन पावर बैंक-अप अनुभव को बदलने के लिए तैयार है, ताकि उपभोक्ताओं की पूरे दिन की बैटरी प्रदर्शन की बढ़ती आवश्यकता को पूरा किया जा सके, जो तेजी से अपने मोबाइल उपकरणों पर अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं। स्मार्टफोन में हार्ड-परफॉर्मंस मीडियाटेक हीलियो जी85 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, इन-बिल्ट हाइपर इंजन गेमिंग टेक्नोलॉजी और 18वॉट ड्यूल आईसी फास्ट चार्ज दिया गया है, जो एक निर्बाध गेमिंग और मल्टीटास्किंग अनुभव प्रदान करता है।

कोरोना के कारण एनएचएआई को हुआ 3,512 करोड़ का राजस्व नुकसान- गडकरी



नई दिल्ली :

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को वित्त वर्ष 2020-21 में कोविड-19 से जुड़े प्रतिबंधों के कारण 3,512.62 करोड़ रुपए के राजस्व के नुकसान का अनुमान है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 में अनुमानित उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह क्रमशः 27,682.89 करोड़ रुपए और 28,548.05 करोड़ रुपए रहा। गडकरी ने कहा, वित्त वर्ष (वित्त वर्ष) 2020-21 में कोविड-19 से जुड़े प्रतिबंधों के कारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को राजस्व के नुकसान का अनुमान है। उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में किसानों द्वारा लगातार जारी विरोध प्रदर्शनों के कारण, वित्त वर्ष 2020-21 में 58 शुल्क प्लाजा 12 दिनों से लेकर अधिकतम 182 दिनों तक बंद थे। इसके चलते 814.13 करोड़ रुपए का अनुमानित नुकसान हुआ।

मंत्री ने कहा, केरल राज्य में त्रिवल्लम शुल्क प्लाजा और ओडिशा राज्य में पदामनपुर और सुखुपाड़ा शुल्क प्लाजा जैसे कुछ प्लाजा पर विरोध की छिटपुट घटनाएं देखी गईं।

फिलपकार्ट को 10,600 करोड़ का नोटिस



नई दिल्ली । विदेशी मुद्रा कानून के कथित उल्लंघन के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ई-कॉमर्स कंपनी फिलपकार्ट और उसके प्रवर्तकों को करीब 10,600 करोड़ रुपए का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की विभिन्न धाराओं के तहत पिछले महीने 10 लोगों को नोटिस जारी किया गया था, जिनमें फिलपकार्ट और उसके संस्थापक सचिन बंसल और बिनी बंसल शामिल हैं। जांच पूरी होने के बाद नोटिस जारी किया गया और कंपनी पर लगे आरोपों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों का उल्लंघन और बहु-ब्रांड खुदरा को विनियमित करना शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वाल्मार्ट के स्वामित्व वाली कंपनी और उसके अधिकारी अब न्यायिक फैसले का सामना करेंगे। एजेंसी के चेन्नई स्थित एक विशेष निदेशक-रैंक के अधिकारी इस कार्यवाही का संचालन करेंगे।

राजस्थान सरकार पर्यटकों को सीमाओं की सुंदरता दिखाने की बनाएगी योजना

जयपुर।

पंजाब से प्रेरणा लेते हुए, राजस्थान पर्यटन जल्द ही सीमा पर्यटन और इसके खूबसूरत खिंचाव को पर्यटकों के लिए उसी तर्ज पर बढ़ावा देगा, जैसा कि पंजाब ने वाघा सीमा पर किया है, जहां साल भर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। राजस्थान पर्यटन के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है और कहा है कि महामारी के बाद की अवधि के दौरान, राज्य नए गंतव्यों को तैयार करना चाहता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की सीमाओं की सुंदरता का अनुभव करना पर्यटकों के लिए एक नया अनुभव होगा। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में सीमा पर अधिक पर्यटक आते हैं। जैसलमेर जिले में राजस्थान में रेगिस्तानी इलाके का सबसे बड़ा क्षेत्र है। जैसलमेर जिला मुख्यालय से 125 किमी पश्चिम में भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तनोत में तनोत राय का मंदिर भारतीय पर्यटकों और भक्तों के लिए मुख्य आकर्षण है। इस मंदिर का रखरखाव बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल) के स्थानीय दल द्वारा किया गया है जो पूजा और भक्ति समारोह करता है। वरिष्ठ पर्यटन अधिकारी ने आईएनएस को



बताया कि बहुचर्चित बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर ने आस्था के इस स्थान को भी चित्रित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय भारत-पाक सीमा जो मंदिर से थोड़ी दूरी पर है, आने वाले पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। इस जगह के पास एक किला भी है जिसे किशनगढ़ के नाम से जाना जाता है, जो ईंटों और गारे से बना है।पास में ही लोंगेवाला का स्थान है, जो 1971 के भारत-पाक युद्ध का गवाह था। भारतीय सेना द्वारा नष्ट किए गए पाकिस्तानी सेना के सैन्य वाहनों और टैंकों को प्रदर्शन के लिए रखा गया है। यहां एक थिएटर भी है जो भारतीय सेना द्वारा चलाया जाता है जिसमें 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की विजय और विजय की फिल्में पर्यटकों के लिए प्रदर्शित की जाती हैं। इस क्षेत्र में घोटाम का किला भी पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है और उनकी उत्सुकता जगाता है। बाड़मेर में मुनाबाद नाम का एक रेलवे स्टेशन चल रहा है जो भारत-पाक यात्रियों की आवाजाही को पूरा करता है। बीकानेर जिले में भारत-पाक

संचालित है। सांचू चौकी पर जाने के लिए घरेलू पर्यटकों को बीकानेर में बीएसएफ से अनुमति लेनी होती है। पर्यटकों को पाकिस्तान की ओर की पोस्ट और संग्रहालय भी दिखाया जाता है। पर्यटकों को भुगतान पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए बीएसएफ द्वारा एक सुविधा प्रदान की गई है।श्रीगंगानगर जिले के क्षेत्र के बारे में श्रीगंगानगर से 18 किमी की दूरी पर स्थित हिंदूमल कोट सीमा चौकी काफी प्रसिद्ध है। चौकी का नाम बीकानेर की तत्कालीन रियासत के प्रमुख दीवान हिंदूमल के नाम पर रखा गया है। इस चौकी पर स्थित रेलवे स्टेशन भी बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यह भारत और पाकिस्तान को रेल मार्ग से जोड़ता है और दोनों देशों के बीच माल के आयात और निर्यात का भी प्रबंध करता है।



छूट का लाभ भी उठा सकते हैं। ये ऑफर सीमित अवधि के लिए ही मान्य है।

जेएसपीएल की स्टील बिक्री जुलाई महीने में 21 प्रतिशत बढ़ी



नई दिल्ली।

निजी क्षेत्र की स्टील निमाता ज़िंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) ने जुलाई महीने में 2021 स्टील की बिक्री में तेज आई है, जो अपने विकास के पथ पर वापस लौट रही है। स्टील की बिक्री साल-दर-साल 5 फीसदी बढ़ी और पिछले साल के इसी महीने के 6.4 लाख टन की तुलना में 21 फीसदी एम-ओ-एम बढ़कर 6.7 लाख टन हो गई है। बिक्री में सुधार इस बात का संकेत देता है कि महामारी की दूसरी लहर के बाद व्यापार सामान्य रूप से फिर से शुरू हो गया, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में विभिन्न स्थानों पर तालाबंदी हुई थी। जेएसपीएल ने जुलाई में 6.5 लाख टन मासिक इस्पात उत्पादन की सूचना दी, जो पिछले वर्ष के

इसी महीने के 6.03 लाख टन की तुलना में 8 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष अधिक है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों से उच्च हाजिर मांग के कारण कुल बिक्री मात्रा में निर्यात का हिस्सा 40 प्रतिशत से अधिक है। शर्मा, प्रबंध निदेशक, जेएसपीएल ने कहा,कोविड से संबंधित व्यवधानों की दूसरी लहर के बावजूद, हम वित्त वर्ष 2022 के लिए 8.25 मिलियन टन के अपने वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ट्रैक पर हैं। इसके अलावा, हम कोविड के मामलों में कमी देख रहे हैं, जो उद्योग और हमारे ग्राहकों को एक बड़ी राहत देगा। प्रभावी टीकाकरण भारत सरकार का अभियान श्रमिकों को निर्माण स्थलों पर लौटने के लिए प्रोत्साहित करेगा और विनिर्माण की गति देने में मदद करेगा, जिससे घरेलू मांग को बढ़ावा मिलने की संभावना है।



शिफ्ट में काम करने वाले पुरुष न रहें

इस खतरे से अनजान

शिफ्ट में काम करने वाले लोगों खासकर पुरुषों को सामान्य की तुलना में सेहत से जुड़े एक बड़े खतरे का रिस्क ज्यादा होता है। हाल में हुए शोध की मानें तो शिफ्ट में काम करने वाले पुरुषों को टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क अधिक होता है। साथ ही जो लोग एक निर्धारित पाली की जगह बदलती हुई शिफ्ट में काम करते हैं उन्हें यह खतरा और भी ज्यादा होता है।



न्यूयॉर्क के लेनोक्स अस्पताल के क्लीनिकल मनोविज्ञानी डॉ. एर्लन मेनेविटज कहते हैं कि यह शोध ज्यादा चौंकाने वाला नहीं है। डॉक्टर काफी समय से महसूस कर रहे थे कि अलग-अलग पालियों में काम करने से शरीर के रसायन प्रभावित होते हैं और इससे आंतों और दिल की बीमारियां हो सकती हैं। यहां तक कि इससे कैंसर की आशंका भी रहती है। अब टाइप-2 मधुमेह को भी इस सूची में जोड़ा जा सकता है। विज्ञानियों ने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए 12 अंतरराष्ट्रीय शोधों का सहारा लिया जिनमें लगभग सवा दो लाख लोग शामिल थे।

मुख्य शोधकर्ता चीन के वुहान में हुआजोंग यूनिवर्सिटी के जुआन ली हैं, उनका कहना है कि इसमें कर्मचारियों के कई पहलुओं को शामिल किया गया है। जैसे पाली कब से कब तक है, बाड़ी मास इंडेक्स (वजन और लंबाई की गणना), परिवार में किसी को मधुमेह था या नहीं और

शारीरिक सक्रियता।

हालांकि नतीजे सीधे-सीधे कुछ नहीं कहते पर पाया गया कि शिफ्ट में काम करने वाले को मधुमेह होने की संभावना नौ फीसदी अधिक है। अगर कमी पुरुष है तो यह आंकड़ा 37 फीसदी हो सकता है।

हालांकि पुरुष मधुमेह की चपेट में क्यों ज्यादा आते हैं इसका कोई साफ कारण नहीं है लेकिन हारमोन टेस्टोस्टेरोन इसमें अहम भूमिका निभाता है।

साथ ही रोटेटिंग शिफ्ट में काम

करने वाले लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा 42 फीसदी ज्यादा होता है। टीम के अनुसार काम का समय बार-बार बदलने से शरीर के लिए सोने और जागने का समय तय करना मुश्किल हो जाता है।

साथ ही कम सोने से शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है जिससे डायबिटीज होती है। पहले के अध्ययन में मोटापे को मधुमेह का कारण बताया गया था। टीम का कहना है कि शिफ्ट में काम करने से कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप बढ़ते हैं।

विज्ञानियों के अनुसार समय-समय पर मधुमेह का टेस्ट कराते रहना ही इस समस्या का निदान है।

ज्यादातर अघेड़ों या बुजुर्गों को होती है। 95 फीसदी मधुमेह रोगी टाइप-2 से

भी पीड़ित होते हैं। इसमें शरीर में ज्यादा ग्लूकोज या शुगर बनने लगता है। टाइप टू में शरीर इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर पाता।

नतीजा मोटापा बढ़ने से होता है। ग्लूकोज सेल तोड़ने के लिए शरीर को ज्यादा इंसुलिन की आवश्यकता होती है। धीरे-धीरे पैक्रियाज इंसुलिन तैयार करने की क्षमता खो देते हैं। नतीजा कई अन्य रोगों की शुरुआत।

अलग-अलग पालियों में काम करने का असर

सोने और जागने का समय तय करना हो जाता है मुश्किल शरीर के रसायन होतेहैं प्रभावित आंतों और दिल की बीमारियां होने का खतरा कैंसर के अलावा टाइप-2 डायबिटीज की चपेट में भी आ सकते हैं।

गंजेपन

ये ठमेशा के लिए छुटकारा दिलाएगा यठ उपाय



सिर पर बाल झड़ गए हैं या गंजेपन ने आपको समय से पहले ही अंकल बना दिया हो निराश न हों, इससे हमेशा के लिए छुटकारा अब और भी सुलभ है।

वैज्ञानिकों ने सीने के बाल को सिर पर ट्रांसप्लांट कर गंजेपन के बावजूद भी बाल उगाने में सफलता प्राप्त की है। इस विधि को उन्होंने फॉलिक्यूलर युनिट एक्सट्रैक्शन का नाम दिया है।

क्यों है अधिक असरदार

अब तक बालों के ट्रांसप्लांट के दौरान सिर के पिछले हिस्से से, जहां बाल अधिक होते हैं, बाल निकालकर सिर के उन हिस्सों पर लगाया जाता है जहां बाल झड़ चुके हों।

यह प्रक्रिया दर्दनाक तो होती ही है, साथ ही इसकी सफलता की गुंजाइश भी पूरी नहीं होती है। अक्सर गंजेपन के दौरान लोगों के सिर के पिछले हिस्से में भी बाल या तो कम होते हैं या फिर कमजोर, इसलिए जरूरी नहीं कि इनका ट्रांसप्लांट पूरी तरह सफल ही हो।

ऐसे में सीने के बालों को सिर पर लगाने की यह विधि अपेक्षाकृत अधिक असरदार है।

कैसे होगा ट्रांसप्लांट

इस प्रक्रिया के अंतर्गत सर्जन मरीज के सीने पर शेव कर बाल निकाल लेता है। इफर इनमें से सेहत फॉलिकल को मरीज के सिर के गंजे भाग पर ट्रांसप्लांट करता है।

सामान्यतः एक बार सिर पर इस विधि से बाल ट्रांसप्लांट करने का खर्च 10,000 पाउंड यानी 10,20,268 रुपए आता है।

रात में जल्दी खाना खाने के ये है

फायदे

रात में भोजन कैसा हो, सेहत के लिए यह जितना जरूरी है, भोजन कब हो जैसा सवाल भी उससे कम जरूरी नहीं है। आमतौर पर डॉक्टरों का मानना है कि रात के भोजन और सोने के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतर सेहतमंद जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में अगर आप अब भी देर रात खाना खाते हैं तो जल्दी भोजन करने के ये 5 फायदे जानने के बाद आप भी जल्दी खाना शुरू कर देंगे।



वजन पर नियंत्रण

अगर आप देर रात खाना खाएंगे तो सुबह का नाश्ता इससे प्रभावित होगा। कई शोधों में यह माना जा चुका है कि सुबह का नाश्ता ठीक से न करने के कारण लोग दिन भर ओवरडाइट करते हैं।

रात के भोजन का आपकी

बॉडी कलॉक व्यवस्थित रखने में बड़ा रोल है जिससे और ओवरडाइट न करें और मोटापे के शिकार न हो सकें।



गैस्ट्रिक संबंधी

समस्याओं से बचाव

अगर आपको गैस्ट्रिक संबंधी समस्याएं अधिक होती हैं तो आप रात में जल्दी खाने की आदत डाल ही लें।

दरअसल, खाने के

ठीक बाद सोने से भोजन का पाचन अच्छी तरह नहीं हो पाता है जिससे हार्टबर्न जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है।

अच्छी नींद के लिए

रात में जल्दी और सेहतमंद भोजन



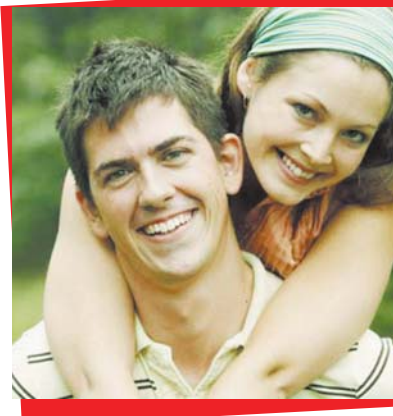
करने से नींद न आने की समस्या को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। यह बॉडी कलॉक को व्यवस्थित रखने में मददगार है जिससे नींद न आने की दिक्कत दूर होती है।

ऊर्जा बरकरार रहती है

देर रात तक देर सारा भोजन करने से आप नाश्ता अच्छी तरह नहीं कर पाते जिससे दिन भर आपको ऊर्जा की कमी महसूस होती है। रात में जल्दी खाने से अगले दिन सुबह का नाश्ता भरपूर होता है जिससे ऊर्जा बनी रहती है।

रोगों से बचाव

कई शोधों में माना जा चुका है कि रात में जल्दी भोजन करने वाले लोगों को हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे दिल के रोगों का रिस्क कम होता है।



चाय में छिपा खूबसूरती का राज



चाय का सेवन कुछ लोग थकान दूर करने तो कुछ आदतन करते हैं, लेकिन चाय की एक प्याली हमारे जीवन के अलग-अलग आयामों के लिए लाभदायक हो सकती है। वेबसाइट फीमेलफर्स्ट डॉट डॉट यूके के मुताबिक, हाल ही में किए गए एक वैज्ञानिक शोध में यह बात सामने आई है कि चाय मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक दृष्टिकोण से लाभदाई होती है। वैज्ञानिकों ने हर किस्म के चाय से जुड़े स्वास्थ्य के सभी फायदे का परीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि यह न सिर्फ शारीरिक सौंदर्य बल्कि वजन कम करने और त्वचा में नमी बरकरार रखने के लिए भी लाभदायी होती है। टी एडवायजरी पैनेल (टीएपी) के विशेषज्ञों ने चाय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं-

त्वचा को नम बनाना - शरीर के अंगों, त्वचा और कोशिका के लिए पानी आवश्यक होता है। नए अध्ययन में पाया गया है कि प्रतिदिन छह कप चाय का सेवन करने से इनकी यह जरूरत पूरी हो जाती है।

स्वस्थ त्वचा में चाय की भूमिका - स्वस्थ त्वचा यानी नम त्वचा। पर्याप्त तरल पदार्थ लेना, जिसमें सभी प्रकार के चाय शामिल हो सकती है, शरीर में तरलता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

क्योंकि खासतौर से गर्मी के दिनों में शरीर से पर्याप्त मात्रा में पानी निकल जाता है। पर्याप्त पानी से त्वचा अच्छे हालात में बनी रहती है।

चाय और वजन घटाना -चाय का सेवन करने से कुछ समय तक वजन ज्यादा नहीं बढ़ता। एक साप्ताह से ज्यादा चाय पीने से चाय न पीने वालों की अपेक्षा वजन कम बढ़ता है। काली चाय, कम मलाई वाले दूध की चाय और बिना चीनी वाली चाय सहित सभी चाय में अन्य चर्चित पेय पदार्थों की अपेक्षा कम कैलोरी होती है।

चाय और खूबसूरती - चाय में हमारी त्वचा की खूबसूरती के लिए पर्याप्त पानी मौजूद होता है और यह वजन घटाने में मदद करता है। एक टी बैग में भी खूबसूरती के राज छिपे होते हैं। टी बैग को गुनगुने पानी में डाल कर फिर इसे बंद आंखों के ऊपर रखने से आंखों को थकान से राहत मिलती है।

अवसाद बढ़ा सकता है अत्यधिक

छोटा या लंबा होना

सेना में अधिक शारीरिक लंबाई और कम लंबाई वाले लोगों में औसत लंबाई वाले अपने सहयोगियों की अपेक्षा अवसाद का खतरा ज्यादा होता है। एक अध्ययन में यह खुलासा हुआ है। शोधकर्ताओं का कहना है कि औसत से अधिक लंबे या कम लंबे पुरुषों में अवसाद की समस्या का खतरा ज्यादा होता है। कैलिफोर्निया के कैप पेंडल्टन स्थित नेवेल हॉस्पिटल की वेलेरी करुपनिक और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की मारिया केरकासोवा ने एक मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक में सेना के ड्यूटी पर तैनात 196 पुरुषों में अवसाद संबंधी बातों का अध्ययन किया। शोधकर्ताओं का अनुमान था कि औसत से कम लंबाई वाले सैनिकों में अवसाद का खतरा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि सेना में शारीरिक कौशल ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके उलट शोधकर्ताओं ने पाया कि अवसाद की समस्या औसत से अधिक लंबे पुरुषों में भी कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि कई बार वे अपनी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। करुपनिक ने कहा, बच्चों के शारीरिक कद को ध्यान में रखकर हमारे यहां विशेष कार्यक्रम नहीं चलाए जाते।

बारिश में जुकाम

से कैसे बचें



इस मौसम में सर्दी-खाँसी आम बात है। तुलसी और अदरक इस मौसम में लाभदायक होते हैं। तुलसी में काफी उपचारी गुण समाए होते हैं, जो जुकाम और फ्लू आदि से बचाव में कारगर हैं। तुलसी की पत्तियाँ चबाने से कोल्ड और फ्लू दूर रहता है। इसी तरह तुलसी और बांसा की पत्तियाँ (प्रत्येक 5 ग्राम) पीसकर पानी में मिलाएँ और काढ़ा तैयार कर लें। इससे खाँसी और दमा में काफी फायदा मिलेगा। अलसी के बीज (लिनसीड) भी खाँसी के इलाज में काफी कारगर होते हैं, क्योंकि ये बलगम बाहर निकालने में मदद करते हैं। इनका काढ़ा बनाकर पी लें या फिर बीजों को पीसकर चाट लें। जल्द राहत के लिए 10 ग्राम अलसी के पिसे बीजों को मुलेठी के चूर्ण में मिलाएँ और 200 मिली पानी में इन्हें पानी के आधा रह जाने तक उबालें। इसमें 20 ग्राम शुद्ध शहद मिलाएँ और गरम-गरम पिएँ। इससे शरीर का बलगम बाहर निकलता है और खाँसी में राहत मिलती है। अदरक की चाय इस मौसम में स्वाद और सेहत दोनों की दृष्टि से अच्छी है।

आरटीआई एक्टिविस्टों को ब्लैकमेलर कहने पर

पूर्व केन्द्रीय सूचना आयुक्तशैलेश गाँधी ने मुख्य न्यायाधीश मप्र हाई कोर्ट जज को लिखा पत्र

क्रांति समय दैनिक

आरटीआईएम्

पूर्व केन्द्रीय सूचना आयुक्तशैलेश गांधी और सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने संयुक्त तौर पर दिनांक 4 अगस्त 2021 को मुख्य न्यायाधीश मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के नाम पर एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने शिवानंद द्विवेदी के ट्विटर वाल पर पोस्ट का हवाला देते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक माननीय जज के द्वारा स्पष्ट तौर पर सुनवाई के दौरान वीडियो क्लिप में कहा जा रहा है कि अधिकतर आरटीआई एक्टिविस्ट ब्लैकमेलर होते हैं। उन्होंने कहा की इसका कोई बौद्धिक और तर्कसंगत आधार नहीं है और यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है जो की एक जिम्मेदार जज के द्वारा कहा गया है। उन्होंने आगे लिखा की आम नागरिक के अनुच्छेद 19(1)(ए) का यह सीधा-सीधा उल्लंघन और दमन है।

श्री गांधी ने आगे लिखा की सूचना के अधिकार का उपयोग करते समय एक भारतीय नागरिक लोकतंत्र के उस वादे को साकार कर रहा है कि वह आम नागरिक सरकार का मालिक हैं। अधिकांश नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार का उपयोग करने के लिए इस प्रकार वरिष्ठ जज द्वारा निंदा करने से उनके मौलिक अधिकार का हनन होगा। न्यायपालिका लगातार नागरिक के मौलिक अधिकार के दायरे का विस्तार कर रही है और न्यायाधीश द्वारा दिए गए बयान को आरटीआई के उपयोग को रोकने और निंदा करने के लिए कई जगहों पर उद्धृत किया जाएगा और इसका आधार बनाकर अपमान किया जाएगा और आर टी आई कानून और इसके उपयोगकर्ता को कमजोर किया जाएगा। उन्होंने कहा की ऐसे बयान का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है और अगर कोई व्यक्ति ब्लैकमेल का सहारा ले रहा है तो उसे कानून द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। बोलते या प्रकाशित करते समय आरोप लगाए जा सकते हैं जो मानहानिकारक हो सकते हैं।

आरटीआई का उपयोग कर नागरिक केवल वही जानकारी प्राप्त कर सकता है जो सरकारी रिकॉर्ड में है। अगर यह कुछ गलत करते हुए दिखता है तो इसे उजागर किया जाना चाहिए। अच्छा होगा यदि अदालतें आरटीआई अधिनियम की धारा 4 द्वारा अपेक्षित अधिकांश सूचनाओं को स्वप्रेरणा से घोषित नहीं करने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण को फटकार लगाती रहें। लोक प्राधिकारियों को धारा 1.4.1 के तहत डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/6/2011-आईआर जिसमें कहा गया है सभी सार्वजनिक प्राधिकरण मुख्य शब्दों के आधार पर सर्व फैसिलिटी के साथ सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा बनाए गए वेबपोर्टल पर आरटीआई आवेदन और प्राप् अपीलों और उनके जवाबों को एक्टिव तौर पर प्रकट करेंगे। श्री गाँधी ने कहा की पारदर्शी होने के इच्छुक हैं तो

ब्लैक मेलिंग की कोई संभावना नहीं होगी। उन्होंने कहा की वह जज महोदय से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हैं कि न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रहरी के रूप में समर्थन करती है।

इस पत्र पर कमेंट करने वाले लोगों में पंकज मालवीय ने कहा कि वास्तव में देखा जाए तो ब्लैकमेलर वह लोग हैं जो जनता की जानकारी को दबाए रखे हुए हैं। वही एक अन्य ट्विटर उपयोगकर्ता बीएस रंगा

राव ने कहा कि हम शैलेश गांधी से 100 प्रतिशत सहमत हैं। रंगा राव ने कहा कि आखिर ब्लैकमेलर को जानकारी क्यों दे रहे हैं ऐसा क्यों नहीं करते कि ऐसे ब्लैकमेलर को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए और उन्हें एक्स्पोज किया जाए। आगे कहा की कानून में गैरकानूनी लोगों के विरुद्ध

*****ट्विटर पर इन इन लोगों ने किया कमेंट*****

पूर्व केन्द्रीय सूचना आयुक्त द्वारा ट्विटर पर मुख्य उपलब्ध हैं और यह कहने से नहीं हो जाता कि न्यायाधीश मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को साझा किए गए आरटीआई उपयोगकर्ता ब्लैकमेलर है। वही अमित

शर्मा ने कहा कि वास्तव में जो स्वयं ब्लैकमेल कर रहे हैं वही ब्लैकमेलर की बात कर रहे हैं सभी अधिकारी कर्मचारी ब्लैक मेलिंग के ही सिद्धांत पर काम कर रहे। एक अन्य उपयोगकर्ता अशोक ओझा ने कहा कि शासकीय कर्मचारियों को आरटीआई आवेदनकर्ता को परेशान नहीं करना चाहिए।

***** ट्विटर**

पर पत्र साझा करने के साथ बड़ी प्रतिक्रियाएं ***

जैसे ही पूर्व केन्द्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने 5 अगस्त 2021 को सुबह लगभग 10:54 पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजा गया पत्र ट्विटर पर साझा किया



Tweet



Shailesh Gandhi
@shaileshgan

RTI users are exercising their fundamental right under Article 19 (1)(a). They are not BLACKMAILERS.

shailesh gandhi

former Central Information Commissioner

B2 Gokul Apartment, Podar Road, Santacruz (W), Mumbai-400054

Tel: 022 26001003; 8976240798

Email: shaileshgan@gmail.com

4 August 2021

To
The Honourable Chief Justice <mphc@nic.in>
Madhya Pradesh High Court
Dear Sir,

We wish to draw your attention to this video clip which is circulating on the internet.
<https://twitter.com/i/status/1421341287886704646>

It is reported to be of the High Court of Madhya Pradesh and the Hon'ble Justice is clearly saying that "Maximum RTI activists are blackmailers". This is a very unfortunate statement without any rational basis. It castigates and condemns citizens using their fundamental right under Article 19 (1)(a). It has been recognised that Freedom of Speech, Freedom to Publish and Right to Information all fall under Article 19 (1)(a). When using Right to Information a citizen is actualising the promise of democracy that they own the government.

Condemning most citizens for using their fundamental right would erode their fundamental right. The judiciary has been consistently expanding the scope of citizen's fundamental right, and the statement made by the Judge will be quoted in many places to curb and condemn use of RTI.

There is no evidence to support the statement, and if there is any individual who is resorting to blackmail he should be punished by law. When speaking or publishing, accusations may be made which may be defamatory. Using RTI the citizen can only get information which is on government record. If it shows some wrong doing it should be exposed.

It would be good if the courts castigate the public authorities for not declaring most information *suo moto* as required by Section 4 of the RTI Act. Public authorities should act as per section 1.4.1 of DOP's OM no. 1/6/2011-IR which states: "All Public Authorities shall proactively disclose RTI applications and appeals received and their responses, on the websites maintained by Public Authorities with search facility based on key words." There would be no possibility of blackmailing if public authorities are willing to be transparent.

We request you to ensure that the judiciary supports citizen's fundamental rights as the sentinel on the qui vive.

Thanking you,

1. Shailesh Gandhi, RTI activist and Former Central Information Commissioner
shaileshgan@gmail.com

-मामले में आरोपी चारों प्रोड्यूसर गहना वशिष्ठ, अजय श्रीमंत, प्रिंस कश्यप और अभिजीत हैं फरार

चार में से 2 प्रोड्यूसरों को सौंपी गई थी पोर्न फिल्मों के लिये लड़कियों को फुसलाने की जिम्मेदारी

-पोर्नोग्राफी मामले में दूसरा केस दर्ज कराने वाली अभिनेत्री के साथ भी इन प्रोड्यूसरों ने यही तरीका अपनाया मुंबई।

पोर्न फिल्में बनाने के आरोपों में गिरफ्तार बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। इस बार उन्हें कंपनी में काम करने वाले चार फरार प्रोड्यूसर्स के कारण पूछताछ से गुजरना पड़ सकता है। मुंबई क्राइम ब्रांच सूत्रों ने जानकारी दी है कि इनमें से दो निर्माता लड़कियों को बहला-फुसलाकर अश्लील फिल्मों में काम करने के लिए तैयार करते थे। पोर्नोग्राफी मामले में दर्ज दूसरी

एफआईआर की जांच में यह सामने आया है। क्राइम ब्रांच सूत्रों के अनुसार कुंद्रा की कंपनी में काम करने वाले और फरार चल रहे 4 प्रोड्यूसरों में से दो को छोटे शहरों से बॉलीवुड में काम करने का सपना लेकर मुंबई आने वाली लड़कियों को फुसलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सूत्रों के मुताबिक, इनका काम लड़कियों को बड़े बैनर में काम का लालच देकर झांसे में लेना और फिर जबरन पोर्न वीडियोज में काम करवाना था। इस मामले में आरोपी चारों प्रोड्यूसर गहना वशिष्ठ, अजय श्रीमंत, प्रिंस कश्यप और अभिजीत फरार हैं, जिनकी तलाश में क्राइम ब्रांच जुटी हुई है।

इन सभी आरोपियों के मोबाइल बंद है। साथ ही वे अपने पते से भी गायब हैं। इसमें से अभिनेत्री वशिष्ठ ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मुंबई के दिंडोशी सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की हुई है, जिस पर 6 अगस्त को सुनवाई की जा सकती है। दूसरी एफआईआर में राज कुंद्रा का नाम भले ही न हो, लेकिन उनकी कंपनी हॉटशॉट्स का नाम है। यही वजह है कि इस मामले में क्राइम ब्रांच जल्द ही राज कुंद्रा से पूछताछ कर सकती है। राज कुंद्रा की कंपनी हॉटशॉट्स के लिए काम करने वाले ये दोनों प्रोड्यूसर छोटे-छोटे शहरों से आने वाली लड़कियों को

बॉलीवुड में बड़े बैनर की फिल्मों में काम दिलाने की बात कहते थे। यह बात सुनकर जब वह काम करने को तैयार हो जाती थीं तो शूटिंग के दौरान अचानक उन्हें न्यूड सीन्स करने को कहा जाता था, जब वह मना कर देती थीं तो फिर उन्हें या तो मजबूर या फिर डरा-धमका कर एडल्ट वीडियोज में काम कराया जाता था। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक पोर्नोग्राफी मामले में दूसरा मामला दर्ज कराने वाली अभिनेत्री के साथ भी इन दोनों प्रोड्यूसरों ने यही तरीका अपनाया। दोनों ने पहले 2020 में बॉलीवुड में बड़े बैनर की फिल्म में काम दिलाने के नाम पर अभिनेत्री से संपर्क

किया। सूत्रों के मुताबिक, अभिनेत्री ने बयान दिया है कि दोनों ने उसे चार शॉर्ट वीडियोज में काम करने के बदले 1 लाख रुपये देने की बात कही। इन वीडियोज की शूटिंग मड आलैंड और लोनावाला के बंगले में होनी तय हुई। उन्होंने कहा कि अगर मैंने उनके साथ काम किया तो वह बड़े बजट की फिल्मों में काम दिलाएंगे। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिया गया, उसमें मुझे सिर्फ 10 हजार पेमेंट की बात लिखी थीज पूछने पर बताया गया कि टैक्स बचाने और कुछ अन्य वजहों से कॉन्ट्रैक्ट में पैसों को कम दिखाया गया है, जिस पर उसने भरोसा कर लिया।



मंत्रिमंडल ने पीएम-वाणी के माध्यम से ब्रॉडबैंड प्रसार के प्रस्ताव को दी मंजूरी

-संचार राज्य मंत्री देवु सिंह चौहान ने लिखित जवाब में राज्यसभा को दी यह जानकारी

नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को कहा कि मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क प्रधानमंत्री वायरलेस एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) के माध्यम से ब्रॉडबैंड प्रसार के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। संचार राज्य मंत्री देवु सिंह चौहान ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने पिछले साल दिसंबर में पीएम-वाणी के माध्यम से ब्रॉडबैंड प्रसार के लिए विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि पीएम-वाणी ढांचा के अनुसार, अंतिम छोर तक ब्रॉडबैंड संपर्क सार्वजनिक वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट्स के माध्यम से प्रदान की जाएगी। पीएम-वाणी के माध्यम से सार्वजनिक वाई-फाई अखिल भारतीय फ्रेमवर्क है एवं यह ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए है। उन्होंने बताया कि गुजरात में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों को मिलाकर स्थापित किए गए वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट्स की कुल संख्या 1981 है।

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में 5,422 किलोमीटर की सड़क निर्माण हो रहा

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने देश के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में 5,422 किलोमीटर की सड़क निर्माण परियोजनाओं का बीड़ा उठाया है। गडकरी ने बताया कि 5,422 किलोमीटर की सड़क परियोजनाओं में से 4,932 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया गया है तथा शेष में काम चल रहा है। मंत्री के अनुसार, नौ राज्यों के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में 5,422 किलोमीटर की सड़क परियोजनाओं पर आने वाली लागत 8,673 करोड़ रुपये है।

ऊंची ब्याज दरों के कारण छात्र शैक्षणिक कर्ज नहीं ले पा रहे

औरंगाबाद । मराठवाड़ा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्वादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के पार्षद सतीश चह्णान ने दावा किया कि ऊंची ब्याज दरों के कारण छात्र शैक्षणिक कर्ज नहीं ले पा रहे हैं, उन्होंने केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड के सामने यह मुद्दा उठाया। चह्णान ने कहा कि उन्होंने डॉ. कराड से मुलाकात कर अनुरोध किया कि शैक्षणिक कर्ज पर ब्याज दरें कम की जाए। उन्होंने कहा कि कराड को लिए ज्ञापन में कहा,मौजूदा ब्याज दर नौ से 13 प्रतिशत के बीच है जो अधिक है जिससे आम जनता के लिए शैक्षणिक कर्ज लेना मुश्किल हो रहा है। कोविड-19 का ग्रामीण इलाकों, खासतौर से किसान समुदाय पर आर्थिक रूप से खराब असर पड़ा है। वे इस लेकर चिंतित है कि वे कैसे कर्ज चुकाएंगे। पार्षद ने रेल राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे से भी मुलाकात कर मराठवाड़ा में रेल परियोजनाओं में तेजी लाने का अनुरोध किया।

विदेश जाने वाले छात्रों की मदद के लिए अदार पूनावाला ने बनाया, 10 करोड़ रुपये का फंड

नई दिल्ली । सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ और मालिक अदार पूनावाला ने कहा कि उन्होंने पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों की मदद के लिए 10 करोड़ रुपये अलग रखे हैं, क्योंकि कुछ देशों ने अभी तक क्वारंटीन के बिना प्रवेश के लिए कोविशील्ड को एक स्वीकार्य टीके के रूप में मंजूरी नहीं दी है। पूनावाला ने लिखा, विदेश जाने वाले प्थि छात्रों, चूंकि कुछ देशों ने अभी भी कोविशील्ड को क्वारंटीन के बिना यात्रा के लिए स्वीकार्य टीके के रूप में मंजूरी नहीं दी है,इसकारण आपको कुछ खर्च करना पड़ सकता है। मैंने इसके लिए 10 करोड़ रुपये अलग रखे हैं। उन्होंने लिंक भी साझा किया, जहां जरूरत पड़ने पर छत्र वित्तीय सहायता के लिए आवेदन दे सकते हैं। अदार ने इससे पहले जुलाई में, प्रवेश के लिए एक स्वीकार्य टीके के रूप में कोविशील्ड को मान्यता देने के लिए 16 यूरोपीय देशों की सराहना की थी।

बाढ़ की विभीषिका देख बोले शिवराज, 70 वर्षों में नहीं देखी ऐसी विनाशालीला

- ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के गांव जलमग्न हुए भोपाल । मूसलाधार बारिश से मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। भारी बारिश के कारण हुए हादसों में गुववार को दो लोगों को मौत गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। राज्य में कई जगहों पर इमारतें और पुल ध्वस्त हो गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि उन्होंने बीते 70 सालों में प्रदेश में ऐसी तबाही नहीं देखी है। राज्य सरकार का कहना है कि बारिश के चलते हुई घटनाओं में अब तक दो लोगों की मौत हुई है। एक व्यक्ति की मौत शिवपुरी और एक की रघोपुर जिले में हुई है। इसके अलावा गुना में 4 और दो शिवपुरी और 1 व्यक्ति मुरैना जिले में घायल हुआ है। कहा जा रहा है कि मौतों और घायलों का आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है। इसकी वजह यह है कि उन्हीं मौतों को सरकार ने आंकड़ों में शामिल किया है, जिनकी पुष्टि जिला प्रशासन से की गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि भारी बारिश के चलते दलिया में रतनगढ़ मंदिर के पास एक पुल टूट गया। इसके अलावा संकुआ में भी एक पुल टूट गया और इसके चलते बड़ी संख्या में लोग बाढ़ में फंस गए थे। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि सीएम ने ग्वालियर और चंबाल संभाग के कमिश्नरों और आईजी से बात की है। सीएम ने बताया कि लोगों को बचाने के लिए शिवपुरी और पिंड जिले में पुरर ऑपरेशन भी चलाया गया है। शिवराज सिंह चौहान के हवाले से एक अधिकारी ने कहा, राज्य ने बीते 70 सालों में ऐसी तबाही नहीं देखी है, जो अब ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में बाढ़ के चलते देखने को मिल रही है। रतनगढ़ माता मंदिर और संकुआ में पुल टूट गए हैं और इन इलाकों में लोग फंस गए थे। बुधवार की रात को प्रशासन ने शिवपुरी जिले के काली पहाड़ी इलाके से 57 लोगों को बचाया।

देश की खाद्यान सुरक्षा को बनाए रखने के लिए तीनों कृषि कानूनों को निरस्त होना जरुरी: प्रियंका गांधी वाड़ा

नई दिल्ली ।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा ने कहा कि अगर देश की खाद्यान सुरक्षा को बनाए रखना है,तब तीनों नए केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करना होगा। उन्होंने ट्वीट किया,किसान फसल उगाता है। महामारी में भी अन्न कम नहीं होने देता। लेकिन धन्यवाद मोदी जी को? मोदी जी काले कृषि कानून लाए हैं, जिससे देश की खाद्यान्न शक्ति को ही खतरा है।’’ कांग्रेस की यूपी प्रभारी ने ट्वीट किया,यदि देश की खाद्यान्न सुरक्षा बनाए रखना है,तब इन कृषि कानूनों को रद्द करके किसानों का सम्मान लौटाना होगा। प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना उस वक्त साधा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक वृहद अभियान की शुरुआत की। उन्होंने इस मौके पर वाराणसी, कुशीनगर, झांसी सुल्तानपुर और सहारनपुर के निवासी कुछ लाभार्थियों से बातचीत की।

जब अपने ही राज्य में प्रवेश कर रहे हैं तो महाराष्ट्र के लोगों से रिपोर्ट क्यों मांगी जा रही है?

-महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा पर शिवसेना ने आरटीपीसीआर नेगेटिव के फैसले के खिलाफ रोका रास्ता

मुंबई।



महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा पर गु्रवार को शिवसेना ने आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के फैसले के खिलाफ रास्ता ब्लॉक कर दिया। हालांकि कुछ देर बाद प्रदर्शन करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार कोल्हापुर स्थित राज्य सीमा पर यह हंगामा हुआ। मामला यह है कि कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया है कि जो गाड़ियां, महाराष्ट्र की ओर से आ रही हैं उनके लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। शिवसेना के कोल्हापुर जिला प्रमुख संजय पवार ने कहा कि उन्होंने कोमोली चेक पोस्ट पर लगभग दो घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आरटीपीसीआर टेस्ट से छूट देने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा, कागल, अजय, चांदगढ़ और गडिंगलाज (महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों) के वाहनों को गांवों और कस्बों में जाने के लिए सीमा चौकी से गुजरना पड़ता

है। उनके पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है। जब वे अपने ही राज्य में प्रवेश कर रहे हैं तो महाराष्ट्र के लोगों से रिपोर्ट क्यों मांगी जा रही है? पवार ने कहा कि कर्नाटक के अधिकारियों ने कहा कि वे अपनी नीति में बदलाव करेंगे। आरटीपीसीआर की जगह आधार कार्ड अनिवार्य किया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने 31 जुलाई को एक विशेष निमंत्रांनी उपाय की घोषणा करते हुए कहा था कि केरल और महाराष्ट्र से राज्य में आने वालों के लिए आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। सरकार द्वारा जारी एक परिपत्र के मुताबिक टीकाकरण की स्थिति के बावजूद इन दोनों राज्यों से आने वालों को आरटीपीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी और यह 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। दिशानिर्देश में कहा गया है कि परिपत्र में कहा गया कि विमान, बस, ट्रेन या व्यक्तिगत वाहनों से कर्नाटक आने वाले सभी यात्रियों के लिए यह प्रमाण-पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। इसमें कहा गया कि केरल और महाराष्ट्र से यहां आने वाली सभी उड़ानों से आने वालों के लिए भी यह अनिवार्य होगा।

(जयपुर)-सोयाबीन की 148477 हेक्टेयर, उड़द की 54026 हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें प्रभावित

जयपुर।

राजस्थान में अब लगातार हो रही ज्यादा बारिश से कोटा संभाग में फसलों को बड़ा नुकसान होने की आशंका है। कृषि विभाग के आकलन के मुताबिक सोयाबीन और उड़द का 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र अतिवृष्टि के चलते प्रभावित हुआ है। कोटा, बारां और बूंदी जिले में उड़द तथा सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान हुआ है। आकलन के मुताबिक 31 जुलाई से 4 अगस्त तक सोयाबीन का 1 लाख 48 हजार 477 हेक्टेयर, उड़द का 54 हजार 26 हेक्टेयर क्षेत्र ज्यादा बारिश से प्रभावित हुआ है। सोयाबीन की

फसल में 10 से 85 फीसदी जबकि उड़द की फसल में 20 से 90 प्रतिशत तक नुकसान होने की आशंका है। सब्जियों की फसल के साथ ही धान, चंवला और तिल की फसल को भी नुकसान हुआ है। फसलों को हुए नुकसान से किसान बेहद मायूस हैं। कोटा में 24 हजार 400 हेक्टेयर में उड़द बोई गई थी, जबकि सोयाबीन की बुवाई 1 लाख 17 हजार 200 हेक्टेयर में की गई थी। कोटा जिले में उड़द का 21 हजार 182 हेक्टेयर क्षेत्र और सोयाबीन का 74 हजार 644 हेक्टेयर क्षेत्र ज्यादा बारिश से प्रभावित हुआ है। कोटा जिले में लाडपुरा, सांगोद, रामगंजमंडी, दीगोद, पीपलडा आदि क्षेत्रों में फसल को क्षति हुई है। बारां जिले में 33 हजार 290 हेक्टेयर में उड़द और 2 लाख 35 हजार 600 हेक्टेयर में सोयाबीन बोई गई थी। यहां उड़द में 9 हजार



758 हेक्टेयर क्षेत्र में और सोयाबीन में 49 हजार 634 हेक्टेयर क्षेत्र में बारिश से क्षति का आकलन किया गया है। बारां जिले में अंता, मांगरोल, बारां, किशंगंज, शाहबाद, अटरू, छबड़ा और छीपावड़ौद क्षेत्र में फसल में नुकसान हुआ है। बूंदी जिले में 70 हजार 800 हेक्टेयर में उड़द और 40 हजार 440 हेक्टेयर में सोयाबीन बोई गई थी। यहां उड़द में 23 हजार 66 हेक्टेयर और सोयाबीन में 24 हजार 199 हेक् टेयर क्षेत्र ज्यादा बारिश से प्रभावित हुआ है। यहां बूंदी, तालेड़ा, के शोरायपाटन, नैनवा, इन्द्रगढ़ और हिण्डौली क्षेत्र में नुकसान हुआ है।

-कोरोना की तीसरी लहर के दृष्टिगत बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही सरकार

महिंद्रा ग्रुप द्वारा प्रदान पांच ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस को सीएम ने किया रवाना

शिमला।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज ओक ओवर से कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत महिंद्रा ग्रुप द्वारा प्रदान की गई पांच ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस को भारी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इसके लिए जय राम ठाकुर ने महिंद्रा ग्रुप का आभार भी जताया। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये एंबुलेंस मरीजों को राहत प्रदान करने के प्रदेश सरकार के प्रयासों में सहायक सिद्ध होंगी।

ये एंबुलेंस आईजीएमसी शिमला, किन्नौर, कंछाघाट, जंजैहली और नुरपुर अस्पताल को प्रदान की जाएगी। उन्होंने जिला कांगड़ा के देहरा में 500 एलपीएम पीएसए आक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए भी महिंद्रा ग्रुप का आभार व्यक्त किया। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी, प्रेजिडेंट महिंद्रा ग्रुप के कार्यकारी सहायक यशवर्धन वर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बताया कि सरकार ने कोविड की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत बच्चों की सुरक्षा और बच्चों के कोविड मामलों के लिए

व्यवस्था करने को प्राथमिकता दे रही है। जिलों और मेडिकल कॉलेजों को पहले ही प्रोटोकॉल भेजा जा चुका है। सुनिश्चित किया जा रहा है, कि एसएससीयू, पीडियाट्रिक एचडीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू को प्राथमिकता के आधार पर कार्यशील किया जाए। सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों और जिला अस्पतालों, नागरिक अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समर्पित कोविड अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं

में वृद्धि करके या उपलब्ध सुविधाओं में बिस्तरों को चिकित्त कर बाल चिकित्सा वाई और नवजात इकाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। इन बिस्तरों को केंद्रीय ऑक्सीजन आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाए। वर्तमान में प्रदेश में 16 स्वास्थ्य संस्थानों में 224 एसएससीयू बिस्तर उपलब्ध हैं। सभी स्तरों पर नवजात और बाल रोगियों के लिए एक उपयुक्त आपातकालीन जांच क्षेत्र और उपचार सेवाएं सृजित करने के निर्देश दिए गए हैं। उपचार से



संबंधित सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे उपचार में उपयोग होने वाली वस्तुएं, ऑक्सीजन स्पॉट, रेफरल स्पॉट, टेलीमैडिसिन सुविधा आदि सुनिश्चित की जा रही हैं। बाल रोग विशेषज्ञों, चिकित्सा अधिकारियों, बाल चिकित्सा देखभाल के लिए

तैनात की जाने वाली नर्सों आदि के लिए भी अस्पताल प्रभारी द्वारा योजना तैयार की जाएगी। विभाग ने एसएनसीयू में सभी अक्रियाशील उपकरणों को जल्द से जल्द क्रियाशील करने के भी निर्देश दिए हैं।